

महंगी हेल्थ सर्विसेस का अब होगा इलाज

आम आदमी को सस्ता और पुख्ता इलाज मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। सरकार ने पिछले दिनों दिल में लगाने वाले स्टेंट्स के रेट फिक्स किए थे। अब 19 मेडिकल डिवाइस के दामों को कंट्रोल करने की दिशा की तरफ कदम बढ़ा लिए हैं। यही नहीं, लैब टेस्ट और इलाज के दामों पर भी लगाम लगाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को खत लिखकर अधिकतम और न्यूनतम रेट तय करने के लिए सुझाव मांगे हैं। ऐसे में डिवाइस और टेस्ट के रेट को लेकर चल रही खुली लूट पर भी शिकंजा कस सकेगा।

इलाज के दाम भी रेडार पर

स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को खत लिखकर कहा है कि वह लैब टेस्ट और सभी इलाज के अधिकतम और न्यूनतम रेट सुझाएं। आरोप हैं कि ज्यादातर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के नाम पर मनमाने पैसे वसूले जाते हैं। ऐसे में सरकार दामों पर लगाम लगाने के लिए रेग्युलेटर भी नियुक्त कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि सरकार तमाम लैब्स और अस्पतालों को सुविधाओं के लिहाज से वर्गीकृत कर उनके रेट तय करना चाहती है।

मेडिकल डिवाइस पर रहेगी नजर

Suresh.Upadhyay@timesgroup.com

19 मेडिकल डिवाइस के दामों को कंट्रोल करने के लिए नैशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने नया आदेश जारी किया है। इसके तहत किसी भी मेडिकल डिवाइस के मैक्सिमम रिटेल प्राइस (MRP) में एक साल में 10% से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो सकेगी। एनपीपीए का कहना है कि नए फॉर्मेट के मुताबिक अब हर कंपनी को मार्केट में बेचे जा रहे अपने मेडिकल डिवाइस के बारे में सरकार को सारी जानकारी देनी होगी। मेडिकल डिवाइस असोसिएशंस, मैनुफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स से 31 मई तक सभी 19 मेडिकल डिवाइस का डेटा जमा कराने को कहा गया है। इसमें कैथटर, हार्ट वॉल्व, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट, इंटरनल प्रॉस्थेटिक रिप्लेसमेंट, इंद्रा ऑक्युलर लेंस, डिस्पोजबल हाइपोडर्मिक नीडल, बोन सीमेंट, सर्जिकल ड्रेसिंग, अम्बिलिकल टेप और स्कैल्प वेन सेट जैसे डिवाइस हैं। सरकार इससे पहले स्टेंट्स की कीमतों में लगाम लगा चुकी है।

लैब टेस्ट के रेट होंगे फिक्स



दामों में इतना फासला क्यों?

लैब में होने वाले टेस्ट	CGHS कार्डधारी	आम आदमी के लिए
लिपिड प्रोफाइल	230 रु.	450 से 1200 रु.
किडनी फंक्शन	259 रु.	500 से 1200 रु.
लिवर फंक्शन	259 रु.	500 से 1200 रु.
विटामिन डी लेवल	600 रु.	1200 से 1800 रु.
HbA1c (शुगर लेवल)	150 रु.	350 से 550 रु.
ब्लड शुगर (F/PP)	54 रु.	न्यूनतम 100 रु.

प्राइवेट अस्पताल और लैब्स सरकारी पैनल को वाजिब दाम पर टेस्ट और इलाज दे सकते हैं तो आम आदमी को क्यों नहीं?

लग सकता है एक साल

माना जा रहा है कि विभिन्न लैब टेस्ट और मेडिकल प्रसीजर्स के रेट तय करने में राज्यों को कम से कम छह महीने का टाइम लग सकता है। इसके बाद राज्यों की रिपोर्ट पर केंद्रीय समिति विचार करेगी और फाइनल रेट तय होंगे। इस पूरी प्रक्रिया में करीब एक साल का समय लग सकता है। अस्पतालों और लैब्स का पक्ष भी इस दौरान सुना जाएगा।